स्लोडाउन का शिकार रही भारतीय अर्थव्यवस्था

दूसरी बात यह कि हमें कहीं ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत है। सरकार इस दूसरी बात को स्वीकार करती है। इनके बगैर नीतियां बनाना अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाता है। उसे पहली आवश्यकता को भी स्वीकार करना चाहिए।

आरती शर्मा।।

भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2017–18 से ही स्लोडाउन का शिकार रही है। लगातार तीन सालों तक जीडीपी की रफ्तार कम होती रही और फिर पिछले साल की भयंकर गिरावट। ऐसे में स्वाभाविक ही मन में सवाल उठता है कि आखिर हमारे जॉब मार्केट का क्या हाल है। सरकारी रिपोर्ट से कुछ हद तक इसका जवाब मिलता है, लेकिन केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से इसी सप्ताह जारी तिमाही रोजगार सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2021) में चुनिंदा नौ गैरकृषि क्षेत्रों में रोजगार 29 फीसदी बढ़कर 3.08 करोड़ हो गया। पहली नजर में प्रभावी लगने वाले इस आंकड़े की चमक थोड़ी कम तब पड़ती है, जब स्पष्ट होता है कि यह संख्या 2013–14 के आर्थिक सेंसस के दौरान दिए गए आंकड़ों की तुलना में है। तब रोजगार की संख्या 2.37 करोड़ दर्ज हुई थी। यानी अगर आंकड़ों द्वारा बताई जा रही सचाई पर गौर करें तो सटीक निष्कर्ष यह नहीं है कि रोजगार में 29 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। उपयुक्त निष्कर्ष यह होगा कि इन सात वर्षों के दौरान सालाना दस लाख रोजगार ही सृजित किए जा सके।

वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2017–18 से ही स्लोडाउन का शिकार रही है। लगातार तीन सालों तक जीडीपी की रफ्तार कम होती रही और फिर पिछले साल की भयंकर गिरावट। ऐसे में स्वाभाविक ही मन में सवाल उठता है कि आखिर हमारे जॉब मार्केट का क्या हाल है। सरकारी रिपोर्ट से कुछ हद तक इसका जवाब मिलता है, लेकिन इसमें कई सारे गैप हैं। सो इस मांग आधारित अनुमान को केंद्र सरकार के हाउसहोल्ड सर्वे पर आधारित लेबर सप्लाई के अनुमान से मिलाते हैं और तब तस्वीर गैर कृषि रोजगार की किल्लत की उभरती है। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की सालाना और तिमाही दोनों रिपोर्टों से जॉब की क्वॉलिटी में गिरावट की पुष्टि होती है। हालांकि कायदे से डिमांड और सप्लाई साइड के अनुमानों की आपस में तुलना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी अवधि अलग–अलग हैं, लेकिन फिर भी इनसे यह अंदाजा मिल जाता है कि रोजगार के मोर्चे पर क्या सीन है।

पीएलएफएस की सालाना रिपोर्ट (जुलाई 2019 से जून 2020) दर्शाती है कि 2018 से रोजगार के पैटर्न में कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों की ओर झुकाव आया है। पीएलएफएस की तिमाही रिपोर्टों में सिर्फ शहरी ट्रेंड कवर किए जाते हैं। ताजा रिपोर्ट (अक्टूबर से दिसंबर 2020) इस बात की पुष्टि करती है कि निश्चित वेतन वाले जॉब में कमी आई है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 की अवधि में सैलरीड जॉब 48.7 फीसदी दर्ज की गई, जो सख्त लॉकडाउन वाली अप्रैल से जून 2020 की अवधि के 52.7 फीसदी से कम थी। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगारी दर भी 10.3 फीसदी थी, जो 2019 की उसी अवधि (7.9 फीसदी) के मुकाबले कहीं ऊंची थी। इन सबसे स्पष्ट है कि भारत में रोजगार का संकट है। इसके मद्देनजर पहली जरूरत यह है कि सारे डेटा नियमित रूप से जारी किए जाएं।

एक सवाल उभरा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। सवाल था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा? इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुरदे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे पांच सौ सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में उक्त ढिंढोरा पिटवा दिया गया।

संपादकीय

एकतरफा जीत तय

मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में बीते हफ्ते हुए नेशनल असेंबली समेत राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। मध्य अमेरिका के सबसे बड़े इस देश में पूर्व मार्क्सवादी छापामार डेनियल ओर्तेगा लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो ओर्तेगा को 76 फीसदी वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी वाल्टर एस्पिनोजा को 14 फीसदी वोट से ही संतोष करना पड़ा। यानी ओर्तेगा बिलकुल ही एकतरफा जीत हासिल करने में कामयाब हुए। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ओर्तेगा को इतनी बड़ी जीत मिली है। पिछली बार 2016 में जब आम चुनाव हुए, तब उनकी पार्टी 'सांदिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट' को 72 फीसदी वोट मिले थे। दरअसल, ओर्तेगा को बड़ी जीत मिली है यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि ओर्तेगा को यह जीत कई तरह के राजनीतिक दावपेंच लगाने के बाद मिली है। ओर्तेगा की चालबाजियों से निकारागुआ में मानवाधिकार हनन के सवाल खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने इस चुनाव को धांधली से ओतप्रोत बताया है। अमेरिका ने तो ओर्तेगा को आर्थिक प्रतिबंध की धमकी भी दी है। सवाल है कि ओर्तेगा ने क्या चाल चली है? अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक चुनाव से पहले ओर्तेगा ने अपने मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेलों में डाल दिया। वहां की पुलिस ने 40 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जिनमें 7 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी थे। इससे चुनाव मैदान में ओर्तेगा को टक्कर देने वाला एक भी उम्मीदवार नहीं रहा और उनकी एकतरफा जीत तय हो गई।

उन्होंने ठान रखा था कि बतौर सीडीएस कार्यकाल पूरा होने तक इन दोनों प्रक्रियाओं को एक मुकाम तक जरूर पहुंचा देंगे। जनरल रावत अप्रिय होने का जोखिम उठाकर भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे।

पूरा देश दे रहा सीडीएस को श्रद्धांजलि

आशा शिखर।।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की बुधवार को एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई असामयिक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनकी अगुआई में सेना एक साथ दो सरहदों पर तनाव से उपजी असाधारण चुनौतियों का बड़ी कुशलता से सामना कर रही थी। देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और एकीकरण (थिएटराइजेशन) की भी प्रक्रिया शुरू करवाई। हालांकि ये दोनों कार्य आसान नहीं थे, इनमें कई सारी जटिलताएं थीं। इसलिए ये प्रक्रिया तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रही थी, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुरूप जनरल रावत एक–एक कर के सभी मुश्किलें दूर करने में लगे हुए थे।

उन्होंने ठान रखा था कि बतौर सीडीएस कार्यकाल पूरा होने तक इन दोनों प्रक्रियाओं को एक मुकाम तक जरूर पहुंचा देंगे। जनरल रावत अप्रिय होने का जोखिम उठाकर भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। वह खुलकर अपनी बात रखने में यकीन रखते थे। इस वजह से उनके कुछ बयानों को लेकर जब–तब विवाद भी होते रहे। उदाहरण के लिए सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान दिए गए उनके बयान को न केवल अनावश्यक बल्कि उनके कार्यक्षेत्र का उल्लंघन भी बताया गया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर

में आतंकवादियों की लिंचिंग को सही ठहराने वाले उनके बयान से भी सहमति नहीं जताई जा सकती। वायु सेना को आर्मी की एक सहायक शाखा बताने वाला उनका बयान भी सैन्य हलकों में बेवजह असंतोष पैदा करने वाला माना गया।

इन सबके बावजूद जनरल बिपिन रावत अपनी रणनीतिक क्षमता, अपने विजन और व्यापक अनुभव की बदौलत कठिन चुनौतियों के बीच सेना का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करते रहे। उन्हें नॉर्थन और ईस्टर्न दोनों कमांड में काम करने का अनुभव था। इसके अलावा वह सदर्न कमांड का भी नेतृत्व कर चुके थे। वह जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगहों पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे थे और 1987 में सुमदोरॉन्गचू में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से हुई झड़प के दौरान उनकी बटालियन अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात थी। ऐसे साहसी, अनुभव संपन्न और दूरदर्शितापूर्ण जनरल का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में इस तरह चला जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कुछ हलकों से साजिश की आशंका भी व्यक्त की गई है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की कयासबाजी से बचा जाना चाहिए। हां किसी तरह के संदेह के लिए गुंजाइश भी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। दुर्घटना के हालात की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटनास्थल से ब्लैकबॉक्स और वॉयस रिकॉर्डर भी बरामद हो चुके हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच में इस मामले का पूरा सच सामने आ जाएगा और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाए जाएंगे। फिलहाल पहली जरूरत जनरल बिपिन रावत की जगह किसी अन्य काबिल ऑफिसर को सीडीएस पद पर नियुक्त करने की है ताकि सेना का यह सर्वोच्च पद अधिक समय तक खाली न रहे। अच्छी बात है कि यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सूडोकु नवताल-5321

मध्यम

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5320 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	6	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

अपना ब्लॉग

आवश्यक मामलों की सुनवाई भी प्रभावित

मोहन। न्यायालयों में अनावश्यक मामले इतने भर गए हैं कि आवश्यक मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। एक तो निर्णायकों की संख्या सीमित, ऊपर से धरती पर संभव सारे संगत और असंगत विषय उच्च न्यायालयों में 'रिट' नामक बाढ़ बनकर भर जाते हैं जिन्हें दाखिल करने की फीस, वकील की फीस खर्च होने और दीर्घकालिक न्यायिक जाँच– प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि वे सब मामले व्यर्थ थे और उनके ऊपर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मगर इतने समय की बर्बादी के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ न्याय कहाँ हुआ ? उधर कानून के कान में जिरह की लम्बी कील ठोंकने की मोटी दृ तगड़ी फीस तो काले लबादे वाले अधिवक्ता ने जनता से वसूल ही ली। न्यायालयों में अनावश्यक मामलों की बाढ़ को देखकर कई बार ये खयाल आता है कि न्यायपालिका के साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा।